

रीवा

05

अप्रैल 2025
शनिवार

दैनिक

मीडिया ऑडिटर



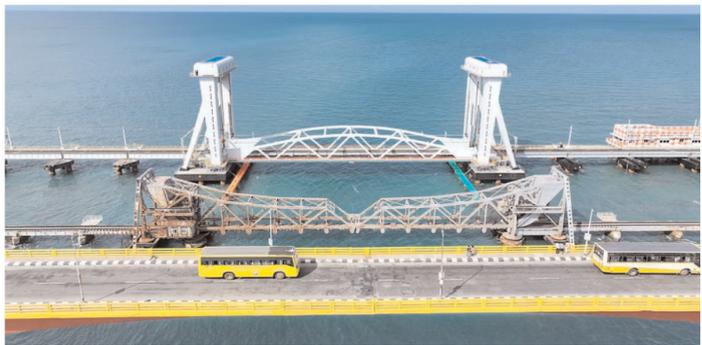
अयोध्या पहुंचकर ...

@ पेज 7

रीवा, सतना से एक साथ प्रकाशित

@ पेज 7

रामनवमी के दिन न्यू पंबन रेल ब्रिज का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन



नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल यानी नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी रामनवमी के अवसर पर रविवार को करेंगे। रोडब्रिज से एक ट्रेन और एक जहाज को

रामेश्वरम में रामनाथस्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे

पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और पुल के संचालन को देखेंगे। उद्घाटन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी रामेश्वरम में रामनाथस्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। बता दें कि पंबन पुल का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। रामायण के अनुसार, राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के



पास धनुषकोडी से शुरू हुआ था। बता दें कि 550 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 2.08 किमी लंबे इस पुल का निर्माण किया गया है जो रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इसमें 99 स्तंभ और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है जो 17 मीटर की ऊंचता तक उठता है, जिससे जहाजों की सुचारु रूप से आवाजाही भी हो सकेगी और

ट्रेन का भी निर्बाध संचालन हो सकेगा। स्टेनलेस स्टील, हाई लेवल के पेंट्स का इस ब्रिज में इस्तेमाल किया गया है। इसे भविष्य की मांगों को लेकर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने बयान में कहा कि दोपहर करीब डेढ़ बजे पीएम नरेंद्र मोदी राज्य में 8300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वह वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस परियोजनाओं का सभी को मिलेगा लाभ सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं में एनएच-40 के 28 किलोमीटर लंबे वाला जंपेट-रानीपेट खंड को चार लेन का

बनाने का शिलान्यास और एनएच-332 के 29 किलोमीटर लंबे बिलुपुरम-पुडुचेरी खंड को चार लेन का बनाने का काम, एनएच-32 के 57 किलोमीटर लंबे पुडियांकुप्पम-सत्तनाथपुरम खंड और एनएच-36 के 48 किलोमीटर लंबे चोलापुरम-तंजावरु खंड को देश को समर्पित करना शामिल है। ये राजमार्ग कई तीर्थस्थलों और पर्यटन स्थलों को जोड़ेंगे, शहरों के बीच की दूरी कम करेंगे और मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बंदरगाहों तक तेजी से पहुंच बनाने के अलावा स्थानीय किसानों को कृषि उत्पादों को नजदीकी बाजारों तक पहुंचाने और स्थानीय चमड़ा और लघु उद्योगों की आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएंगे।

संक्षिप्त समाचार

बैंकॉक में भगवान बुद्ध मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा

बैंकॉक (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बैंकॉक के वात फो मंदिर गए, जो अपनी वास्तुकला और लंबे हुए बुद्ध की 46 मीटर लंबी विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतांगतान शिनावत्रा भी उनके साथ थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने लंबे हुए भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की और मंदिर में वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं को 'संघदान' दिया। प्रधानमंत्री ने लंबे हुए बुद्ध के मंदिर को अशोक के सिंह स्तंभ की प्रतिकृति भी भेंट की तथा भारत और थाईलैंड के बीच मजबूत और जीवंत, सभ्यतागत संबंधों को याद किया। इसके साथ ही उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने यात्रा की तस्वीरों



के साथ 'एक्स' पर जारी एक पोस्ट में कहा, "सदियों पुराना एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पैतांगतान शिनावत्रा के साथ वात फो मंदिर में लंबे हुए बुद्ध के ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया और दिव्य आशीर्वाद मांगा।" वात फो मंदिर के चतुर्भुज विमोचनमंगलाराम रत्नचोराहाहविहान-वात फो में लंबे हुए बुद्ध के ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया और दिव्य आशीर्वाद मांगा। वात फो चतुर्भुज विमोचनमंगलाराम रत्नचोराहाहविहान को वात फो के नाम से जाना जाता है। यहां थाईलैंड में बुद्ध की छवियों का सबसे बड़ा संग्रह है और यह देश का सबसे पुराना सार्वजनिक शिक्षण केंद्र है।

वर्ल्ड ऑर्डर बदलते ही भारत से दोस्ती को बेताब हुआ चीन

बीजिंग (एजेंसी)। दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते ही चीन का झुकना भारत की ओर बढ़ता ही जा रहा है। जबकि अभी तक जून 2020 में गलवान घाटी हिंसा के बाद से बीजिंग भारत के प्रति कड़ ख रुख अपनाए हुए था। मगर अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की वापसी, अमेरिका-रूस में बढ़ती नजदीकियां, पीएम मोदी के ट्वीट और पुलिन से मजबूत रिश्ते जैसे तमाम कारकों ने वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख दिया है। ऐसे में अब चीन को भारत के साथ संबंध बना कर रखने में ही मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी, बेलजियम की वर्कर्स पार्टी, फ्लस्तीनी पीपुल्स पार्टी और अमेरिका, फ्रंस और जर्मनी की कम्यूनिस्ट पार्टियों ने भी माकपा को शुभकामना सेंडें भेजे हैं। चीन की सीपीपी ने अपने संदेश में कहा कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, चीन-भारत संबंधों में सुधार दोनों देशों और क्षेत्र के साझा हित में है।



अलावा चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी (सीपीपी) ने मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (माकपा) को भी इस बखत सेंडें भेजा है। इसमें सीपीपी ने कहा है कि भारत-चीन संबंधों में सुधार दोनों देशों और क्षेत्र के हित में है। सीपीपी ने इसी के साथ म्यूटुअल आर्योजित माकपा के सम्मेलन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (माकपा) द्वारा साझा किए गए एक दस्तावेज के अनुसार, दुनिया भर की 34 कामगारी पार्टियों ने उसे 24वीं पार्टी कांग्रेस (सम्मेलन) की सफलता के लिए शुभकामना सेंडें भेजे हैं। सीपीपी के अलावा, कोरिया की वर्कर्स पार्टी, वियतनाम की कम्यूनिस्ट पार्टी, क्यूबा की कम्यूनिस्ट पार्टी, ऑस्ट्रेलिया की कम्यूनिस्ट पार्टी, बेलजियम की वर्कर्स पार्टी, फ्लस्तीनी पीपुल्स पार्टी और अमेरिका, फ्रंस और जर्मनी की कम्यूनिस्ट पार्टियों ने भी माकपा को शुभकामना सेंडें भेजे हैं। चीन की सीपीपी ने अपने संदेश में कहा कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, चीन-भारत संबंधों में सुधार दोनों देशों और क्षेत्र के साझा हित में है।

वक्फ बिल का विरोध, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति मुर्मू से तत्काल मिलने का वक्त मांगा

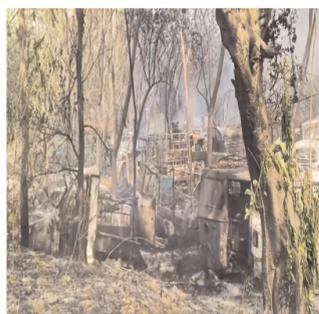
नई दिल्ली (एजेंसी)। वक्फ संशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया गया है। हालांकि, विपक्षी दल और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन इस बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को देश के कई बड़े शहरों में वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। वहीं, अब दृष्टिकोण वक्फ संशोधन बिल को लेकर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल मुलाकात का समय मांगा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन बिल पर अपनी चिंता जताने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल मुलाकात का समय मांगा है, इससे पहले कि राष्ट्रपति इस बिल को मंजूरी दें। दृष्टिकोण के प्रवक्ता डॉ. एस क्यू आर इलियास ने बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहम मुहजदी की ओर से लिखे गए पत्र के विषय को शेयर करते हुए लिखा-

अधिनियम द्वारा पेश किए गए संशोधन में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं जो वक्फ संस्थान के प्रशासन और स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से धार्मिक और धर्मार्थ गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्र में आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति से मिलने का हमारा मकसद हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 और देश भर के मुस्लिम समुदाय के लिए इसके निहितार्थ के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना है। बोर्ड ने आगे कहा- यह अधिनियम पूरी तरह से असंवैधानिक है और देश के मुसलमानों पर हमला है।

दिल्ली पुलिस के मालखाने में लगी भीषण आग

100 से भी ज्यादा गाड़ियां जलकर हुईं खाक

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित पुलिस मालखाने में गुरुवार दोपहर आग लगने से ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त की गई 100 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना के सिलसिले में एक खट्टक दर्ज की गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। उन्होंने बताया कि आग लगने के संबंध में दोपहर 2 बजकर 2 मिनट पर फोन आया था। शुरू में दिल्ली फायर सर्विस यानी कि एम्ब्रस ने कहा था कि मालखाने में खुले क्षेत्र में रखे दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया गाड़ियों सहित लगभग 50 गाड़ियों में आग लगी है।



पुलिस सूत्रों ने बताया कि आग को पूरी तरह से बुझाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अंदाजा है कि 100 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। उन्होंने कहा, 'शुरु में पुलिस ने दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर भेजी थीं। सूचना मिली है कि आग में कुछ ऐसी गाड़ियां भी जल गईं, जिन्हें आपराधिक मामलों में जब्त किया गया था।' वहीं, एम्ब्रस के अधिकारी ने कहा, 'आग की लपटों पर काबू पाने में तीन घंटे से भी ज्यादा का समय लगा। घटना की जांच की जा रही है।' सूत्रों ने बताया कि यह मालखाना दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का है और ट्रैफिक

हेडक्वार्टर के अधिकारी प्रभावित गाड़ियों की संख्या की जांच करने के लिए तुरंत मौके पर पहुंच गए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट से पता चलता है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में जब्त की गई दोपहिया और चारपहिया गाड़ियां (जिनमें दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियां भी शामिल हैं) इस मालखाने में रखे गए थे। आग लगते ही पूरे इलाके में धुंध फैल गया, जो दूर से ही दिखाई दे रहा था।

लगातार खराब हो रही गाजीपुर लैंडफिल की हालत

एनजीटी की रिपोर्ट में डराने वाले खुलासे

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल की हालत लगातार खराब होती जा रही है। एनजीटी की रिपोर्ट में कई हेरान करने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, गाजीपुर लैंडफिल के चारो तरफ दीवार नहीं है, इसकी ऊपरी सतह पर दरारें पड़ रही हैं। वहीं, यहां से निकलने वाला पानी यमुना में जाकर मिल रहा है। 70 एकड़ में फैले गाजीपुर लैंडफिल की निगरानी एमसीडी करती है और पूर्वी दिल्ली का कचरा यहीं डंप किया जाता है। यह जगह पोल्ट्री मार्केट, मछली मार्केट, डेयरी और सब्जी मार्केट, बूचड़खाने और कचरे से एनजी बनाने वाले (डब्ल्यूटीई) संयंत्र से घिरी हुई है। गाजीपुर लैंडफिल में गर्मी के समय आग लगने की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। पिछले साल भी ऐसी कई घटनाएं हुई थीं। इसके बाद एनजीटी ने इस मामले पर



स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट के अनुसार, लैंडफिल की ऊंचाई 40 मीटर से बढ़कर अब 60 मीटर से अधिक हो गई है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, 2017 में लैंडफिल की ऊंचाई 50 मीटर थी। एमसीडी अधिकारियों के अनुसार, इस लगने की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। पिछले साल भी ऐसी कई घटनाएं हुई थीं। इसके बाद एनजीटी ने इस मामले पर

मुंबई कांग्रेस को पुलिस ने भेजा नोटिस

नहीं भरा था AICC इंगार्ज सीक्रेटरी के होटल स्टे का बिल

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कांग्रेस के हाल-बेहाल नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने अब एक मामले को लेकर मुंबई कांग्रेस को नोटिस दिया है। यह नोटिस एक होटल का बिल न भरने को लेकर दिया गया है, बता दें कि मुंबई कांग्रेस की हालत को लेकर पिछले दिनों भी खबर आई थी कि उन्होंने बिजली बिल नहीं भरा था तो मुंबई कांग्रेस के दफ्तर की बिजली गुल होने की नौबत सामने आ गई थी। अब नया मामला होटल बिल को लेकर है।

जानकारी दे दें कि, ड्यूट्ट इंगार्ज सीक्रेटरी इस होटल में रुके थे, जिसका पूरा डिटेल होटल ने पुलिस को दिया है। साथ ही बताया कि होटल का पूरा बिल 51,115 रुपये बना है जो मुंबई कांग्रेस के एक पदाधिकारी की ओर से नहीं दिया जा रहा। होटल ने मुंबई कांग्रेस के पदाधिकारी का नाम भी शिकायत में बताया। शिकायत के बिले पाले पुलिस स्टेशन में दी गई है। पुलिस को दी गई शिकायत में होटल की ओर से कहा गया कि हम कांग्रेस के



पदाधिकारी से मार्च 2024 से पेंडिंग बिल को लेकर फॉलोअप कर रहे हैं। हम जब भी कॉल करते हैं वे हमें वादा करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर हम पेमेंट कर देंगे। ऐसा करते-करते आज 5 माह हो चुके हैं और अब तक हमें यह पेमेंट नहीं मिले। आगे कहा कि काफी फॉलोअप करने पर हमें 14 जून 2024 को पदाधिकारी की ओर से बिना किसी तारीख और साइन के एक चेक दिया गया और कहा गया कि अभी साइन करने वाले पदाधिकारी दिल्ली गए हैं जो 6-7 दिन में आ जाएंगे फिर



आपके चेक पर साइन हो जाएगा। इसके बाद हम उन्हें 3-4 दिन के अंतरात पर कॉल-मैसेज करते हैं। करीबन 10-15 दिनों से अब वे हमारा फोन नहीं उठा रहे और न ही हमारे किसी मैसेज का रिप्लाई दे रहे। जानकारी दे दें कि मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष सांसद वर्धा गायकवाड़ हैं। इससे पहले भी मुंबई कांग्रेस के खस्ताहाल आर्थिक स्थिति का मामला उठा था, पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी वर्षा गायकवाड़ पर लापरवाही पर आरोप लगाया था।

बच्चे के मुंडन के दिन पति-पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

इटवा (एजेंसी)। यूपी के इटवा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बच्चे के मुंडन के दिन पति-पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। ये पति-पत्नी पहले रिश्ते में देवर-भाभी थे लेकिन बाद में इन्होंने आपस में शादी कर ली थी। मामला इटवा के बकेवर थाने के हरराजपुर का है। यहां गृह कलेश के चलते देवताने ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक साल पहले मृतक 23 वर्षीय विशाल बाथम ने अपने बड़े भाई राहुल की पत्नी यानी अपनी भाभी रोशनी (उम्र 25 साल) से विवाह कर लिया था। तभी से दोनों किराए के मकान में रहे रहते थे। आज शुक्रवार को घर के अंदर पहले रोशनी ने साड़ी के फंदे से आत्महत्या की। उसके बाद पति जब अपने बच्चे श्रंयांश का दूध लेकर घर आया तो देखा कि पत्नी रोशनी का शव फंदे पर लटका है।



विचार

स्वास्थ्य बीमा से वंचित 82 प्रतिशत दिव्यांगों को 'आयुष्मान भारत' के साथ जोड़ने की जरूरत

भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना को चलाने वाली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की वैबसाइट पर देश में 76,54,49,221 आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाने का दावा किया गया है। इनमें से 52,08,653 लोगों का हेल्थ डाटा भी इन कार्ड्स के साथ लिंक करने की बात कही गई है। सरकार का दावा है कि इस योजना से करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी योजना देश में लागू होने के बावजूद एक ऐसा वर्ग इस योजना का फायदा लेने से चूक रहा है जो शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं है। 'राष्ट्रीय दिव्यांगता नेटवर्क' द्वारा हाल ही में पेश की गई 'नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपुल' (एन.सी.पी.ई.डी.पी.) की एक सर्वे रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि 82 प्रतिशत दिव्यांगों के पास किसी प्रकार का कोई सेहत बीमा नहीं है और 42 प्रतिशत दिव्यांगों को सरकार की आयुष्मान भारत योजना की जानकारी ही नहीं है। इस सर्वे में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5,000 से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों की राय ली गई है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 28 प्रतिशत दिव्यांगों ने ही आयुष्मान भारत की योजना का लाभ लेने की कोशिश की। एन.सी.पी.ई.डी.पी. के कार्यकारी निदेशक 'अरमान अली' ने कहा कि सर्वे की संख्या महज आंकड़े नहीं हैं बल्कि उन लोगों की हालत दर्शाती है जो आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल से वंचित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेषाधिकार ही नहीं, यह जीवन-यापन के लिए एक आवश्यकता है और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में दिव्यांगों के इस अधिकार की रक्षा करने वाला फैसला भी सुनाया था। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस 'प्रतिभा सिंह' ने 'सौरभ शुक्ला' बनाम 'मैक्स बूपा हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस' और अन्य के मध्य चले एक मामले की सुनवाई के दौरान 13 दिसम्बर, 2022 को सुनाए गए अपने फैसले में कहा था कि जब हम जीवन के अधिकार की बात करते हैं तो उसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल होता है। अदालत ने अपने फैसले के दौरान 'इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी आफ इण्डिया' (आई.आर.डी.ए.) को आदेश दिया था कि वह सभी इंश्योरेंस कंपनियों की एक बैठक करके उन्हें दिव्यांगों के लिए स्वास्थ्य बीमा की योजनाएं जारी करने का आदेश दे लेकिन अदालत के इस फैसले के बावजूद 3 साल तक इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ है। दिव्यांगों के बीच अपने स्वास्थ्य अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी का भी बीमा कंपनियों फायदा उठा रही हैं और उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस जैसे स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। 'अरमान अली' ने सरकार के मानदंडों पर भी सवाल उठाया और कहा कि आयुष्मान भारत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित करता है, लेकिन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

'दोपहिया वाहन के साथ देने पड़ेंगे दो हेलमेट' 'लेकिन सती से इसे लागू करना होगा'

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री 'नितिन गडकरी' देश के उन चंद नेताओं में से एक हैं जो न सिर्फ स्वच्छ राजनीति के पैरोकार हैं बल्कि अपने विभाग के काम को भी संजीदगी से लेते हैं। देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कार चालकों की जान बचाने के लिए 2023 में उन्होंने स्वदेशी कार क्रैश टैस्ट प्रोग्राम 'भारत न्यू कार असैसमेंट प्रोग्राम' (भारत एन कैप) लांच किया था, जिसके परिणामस्वरूप भारत अब अमरीका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद इस तरह का 'कार क्रैश टैस्ट प्रोग्राम' लागू करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन चुका है। इसके अंतर्गत कार निर्माताओं को कार की मजबूती की जांच करने के लिए कार का 'क्रैश टैस्ट' करवाना अनिवार्य है। कारों के 'क्रैश टैस्ट' के बाद 'भारतीय वाहन निरीक्षण और प्रमाणन एजेंसी' (ए.आई.ए.सी.टी.) तथा भारत सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कार की मजबूती के आधार पर उसे 'सिंगल स्टार' से 'फाइव स्टार' तक की रैंकिंग देते हैं।



इस रैंकिंग से ग्राहकों को कार खरीदते समय उसकी मजबूती की पूरी जानकारी हासिल होती है। इस प्रोग्राम से पूरे भारत में कार चालकों की सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित मौतों और घायलों की संख्या कम होने की उम्मीद है। अब 'नितिन गडकरी' ने सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दोपहिया वाहन के साथ खरीदार को अनिवार्य रूप से 'आई.एस.आई. मार्क' वाले दो हेलमेट देने की नीति की घोषणा की है। दिल्ली में आयोजित एक 'ऑटो सम्मिट' में उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 'टू व्हीलर हेलमेट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन' (टी.एच.एम.ए.) के अध्यक्ष 'राजीव कपूर' ने 'नितिन गडकरी' की इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि यह नियम मौजूदा समय में देश की आवश्यकता है। उन्होंने 'नितिन गडकरी' की इस पहल को सड़क सुरक्षा में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह कदम भारत में सुरक्षित और समझदारी भरी दोपहिया यात्रा के नए युग की शुरुआत करेगा। 'श्री राजीव कपूर' ने कहा कि वाहन चालक और सहयात्री यदि हेलमेट पहन कर यात्रा करेंगे तो इससे उनमें सुरक्षा के साथ-साथ जिम्मेदारी का भाव भी आएगा। हेलमेट निर्माताओं द्वारा देश भर में ऐसे उच्च सुरक्षा मानकों वाले हेलमेट की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न पहनने के अलावा वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना भी सड़क दुर्घटनाओं के एक बड़े कारण के रूप में सामने आ रहा है।

हालांकि, इस तरह की लापरवाही के लिए वाहन चालक का चालान काटने का कानूनी प्रावधान है लेकिन पुलिस कर्मियों की संख्या कम होने के कारण इस तरह की लापरवाही भी नहीं रुक रही। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए इस तरह के कानूनी अपराध पर भी सख्ती की जरूरत है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में भारत का दुनिया में पहला स्थान है। 2022 में भारत में कुल 4.61 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1.68 लाख लोगों की मौत हुई। इनमें से 50,000 से ज्यादा मौतें बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों की थीं जिनमें 18 से 45 वर्ष के बीच की उम्र के 35,692 दोपहिया वाहन चालक और 14,337 सहयात्री शामिल थे। उसी वर्ष बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे कुल 1,01,891 चालक और उनके सहयात्री घायल भी हुए थे। घायल होने वालों में 63,584 चालक और 38,307 सहयात्री शामिल थे। इसी प्रकार 2023 में भी भारत में हुई कुल 4.80 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1.72 लाख लोगों की मौत हुई। बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों की दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने की नीति में पिछले दो महीनों में यह दूसरा बड़ा प्रयास है। जनवरी महीने में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न देने की नीति लागू की थी। 'नितिन गडकरी' का यह प्रयास अपने आप में सराहनीय है लेकिन राष्ट्र स्तर पर इसे उत्तर प्रदेश सरकार की तरह सख्ती से लागू करने की जरूरत है, ताकि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों की होने वाली मौतों को रोकना सुनिश्चित किया जा सके।

बुलडोजर न्याय-न्यायिक व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता

तापमान बढ़ने के साथ राजनीतिक भारत में भी गर्मी बढ़ रही है और इसका कारण अभूतपूर्व बुलडोजर राजनीति है। इस भारी भरकम मशीन ने गौरव प्राप्त कर लिया है क्योंकि भाजपा ने बुलडोजर की शक्ति को न केवल एक निर्जीव मशीन की शक्ति के रूप में, अपितु एक राष्ट्रवादी राजनीति के विचार के रूप में प्रस्तुत किया है और यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह एक सुदृढ़, निर्णायक, अच्छे और प्रभावी शासन का अंग है और इस तरह उसने कानून के शासन को कानून द्वारा शासन में बदल दिया है। इस भारी भरकम बुलडोजर को राजनीतिक चर्चा में लाने का श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बनाम बुलडोजर बाबा को जाता है और वर्ष 2017 से वहां सांप्रदायिक दंगाइयों और अपराधियों के विरुद्ध इसका उपयोग किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदायों के घरों को तोड़ने में इसकी सफलता के चलते अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी इसका समर्थन होने लगा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर को क्रमशः बुलडोजर मामा और बुलडोजर ताऊ के रूप में जाना जाता है। उसके बाद दिल्ली, असम, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और पंजाब ने भी राज्य प्रतिकार के रूप में बुलडोजर मॉडल को अपना लिया है। इसका कारण क्या है? मुंबई और नागपुर में सांप्रदायिक झड़पों के बाद मुस्लिमों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को तोड़ा गया। पटियाला, लुधियाना, मोहाली में तस्कर मादक द्रव्यों को बेचकर घर बना रहे हैं। यही नहीं, विपक्ष शासित राज्यों में भी धुवीकरण बढ़ गया है। कांग्रेस शासित हिमाचल के शिमला के संजोली में एक मस्जिद को गिराया गया और इसी तरह कर्नाटक के हुबली में दंगाइयों के घरों को तोड़ा गया।

वर्ष 2022-23 में बुलडोजर द्वारा 1,53,820 और वर्ष 2024 में 7,407 घर गिराए गए और इनमें सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद दिल्ली, गुजरात और असम का स्थान आता है। गिराए गए घरों में 37 प्रतिशत घर मुसलमानों के हैं या मुस्लिम क्षेत्रों के हैं। इस बुलडोजर राजनीति ने एक बड़ा विवाद भी पैदा किया। विपक्ष इसे संविधान का किया जा रहा है। यहां पर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का न केवल दमन किया जा रहा है, अपितु ऐसा करने के बाद उत्साह का वातावरण भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं कि देश की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, बुलडोजर बनेगा हथौड़ा।

प्रश्न उठता है कि क्या यह राजनीतिक बाहुबल और दादागिरी का प्रदर्शन है या यह कानूनी है और दंगाइयों के विरुद्ध एक प्रतिरोधक है। हमारी लोकतांत्रिक जागरूकता इतनी कमजोर बन गई है कि ऐसे उदाहरण मानदंड और सिद्धांत बनते जा रहे हैं और स्थापित कानूनी सिद्धांतों का इस भारी भरकम मशीन द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है और यह एक राजनीतिक औजार बन रहा है जिसका उपयोग एक मजबूत नेता को छवि बनाने के लिए भी किया जा रहा है और इससे सामाजिक मतभेद भी बढ़ रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने एक उल्लेखनीय निर्णय देकर बुलडोजर कार्रवाई पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। न्यायालय ने कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया का उपयोग किए बिना कथित अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के आधार पर किसी व्यक्ति की संपत्ति को गिराना असंवैधानिक है और यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों तथा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को 15 दिन का नोटिस देना होगा और उसकी बात सुनी होगी। किंतु विभिन्न राज्यों की सरकारों न्यायालय के निर्णय को नजरअंदाज कर रही हैं। इससे न्यायिक व्यवस्था के बारे में गंभीर चिंता पैदा होती है। इससे भी अधिक डरना है कि यह है कि कार्यपालिका न्यायालय के निर्णयों का पालन करने में विफल रही है। इससे न केवल कानून का शासन कमजोर हो रहा है अपितु न्यायालय की अविमानता के लिए एक खतरनाक पूर्वोदाहरण स्थापित हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि न्याय के इस स्वरूप में न तो उचित प्रक्रिया के लिए सम्मान है और न ही समय। इस संस्थानगत कदम से न केवल कानून के शासन को खतरा पैदा हो रहा है अपितु इसके अंतर्गत दमनकारी नीतियों को भी अपनाया जा रहा है जो लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है।

ट्रंप के डर से होगी हमारे किसान की लिचिंग?

मोदी राज में किसान की यही नियति बन गई है। एक मुसीबत से जान छूटी तो दूसरी तैयार। ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने तीन किसान विरोधी कानूनों को हराया। इधर किसान एम.एस.पी. हासिल करने के लिए लंबे संघर्ष की तैयारी में जुटे लेकिन उधर सरकार इन्हीं कानूनों को पिछले दरवाजे से लाने के लिए नेशनल फ़ेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मसौदा लेकर खड़ी हो गई। किसान संगठनों के पुरजोर विरोध के चलते इस मोर्चे पर ब्रेक लगी। इतने में नई मुसीबत आन खड़ी हुई। अब भारत सरकार अमरीका के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता करने जा रही है। इसकी गाज भारत के किसान पर पड़ेगी। अगर आने वाले कुछ महीनों में देश के किसान एकजुट होकर प्रतिरोध नहीं करते, तो किसान के भविष्य पर एक बार फिर संकट मंडरा सकता है।

25 से 29 मार्च तक ब्रैंडन लिंच के नेतृत्व में अमरीका के वाणिज्य विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया। एजेंडा था अमरीका और भारत के बीच एक द्विपक्षीय समझौते की रूपरेखा तैयार करना। भारत आकर लिंच ने अपने राष्ट्रपति ट्रंप की तर्ज पर भारत के ही प्रधानमंत्री को आंखें दिखाई। भारत सरकार ने चूं नहीं की। चार दिन की बातचीत को गुप्त रखा गया। आखिर में एक चिकना-चुपड़ा बयान जारी हो गया। लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जानकार बता रहे हैं कि भारत सरकार ने अमरीका

के सामने घुटने टेक दिए हैं। अमरीका भारत की बांह मरोड़ रहा है कि रूस से सस्ता कच्चा तेल लेने की बजाय महंगे बाजार भाव पर अमरीका से कच्चा तेल खरीदे। भारत सरकार पहले ही अमरीका से प्राकृतिक गैस लेने की हामी भर चुकी है। भारत के वाणिज्य मंत्री देश के उद्योगपतियों से अपील कर रहे हैं कि वे अपनी जरूरत का माल चीन से खरीदने की बजाय अमरीका से खरीदें। दिन-रात राष्ट्रवाद की दुहाई देने वाली मोदी सरकार अमरीकी साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेके बैठी है। इस प्रतिनिधिमंडल के अचानक भारत आने के पीछे की कहानी छुपी नहीं है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। आज 2 अप्रैल से अमरीका ने दुनिया के हर देश पर जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। यानी जो देश अमरीका के आयात पर जितना शुल्क लगाता है, अमरीका भी उस पर उतना ही शुल्क लगाएगा। यही नहीं, जो देश अमरीका की विदेश नीति से सहमत नहीं होगा, उस पर विशेष शुल्क लगाया जाएगा। जब प्रधानमंत्री मोदी अमरीका गए तो उनके सामने ट्रंप ने विशेष रूप से कहा कि भारत अमरीकी माल पर बहुत ज्यादा शुल्क लगाता है और अमरीका उसे ठीक करवाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ समय की मोहलत मांगी। कहा कि हम कुछ महीने के भीतर ही अमरीका से एक व्यापक समझौता करेंगे। फिर भी अमरीका ने 2 अप्रैल की जवाबी कार्रवाई



से भारत को मुक्त नहीं किया। साथ में इस प्रतिनिधिमंडल को भेजकर भारत सरकार पर दबाव बनाया है। सवाल यह है कि ब्रैंडन लिंच के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल के दबाव के चलते क्या भारत के किसान के हितों की लिचिंग होगी? कृषि मामलों के जानकार और 'रूरल वॉइस' के संपादक हरवीर सिंह ने यह आशंका जताई है। उन्होंने याद दिलाया है कि हमारी सरकारों ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों से

कृषि क्षेत्र को बाहर रखा है। साथ ही सरकार को आगाह किया है कि इस वार्ता में कृषि उत्पाद को शामिल करने से भारत के किसान को नुकसान पहुंच सकता है। यह आशंका आधारहीन नहीं है। पिछले कई वर्षों से अमरीका की नजर भारत के कृषि उत्पाद बाजार पर रही है। कृषि विशेषज्ञ हरीश दामोदरन ने अमरीका के कृषि व्यापार का विश्लेषण कर बताया है कि पिछले कई साल से चीन ने अमरीकी कृषि उत्पाद की खरीद कम कर दी है और

अब ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों से खरीदना शुरू कर दिया है। इसलिए अमरीका को नए बाजार की तलाश है, उसकी नजर भारत पर है। अमरीका के कृषि मंत्रालय ने बाकायदा भारत के मांस उद्योग का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत में आने वाले दशक में चिकन फीड और पशुओं के लिए सोयाबीन और मक्का की मांग बढ़ेगी। यहां अमरीकी माल के खपत की अच्छी गुंजाइश है। अमरीका के

लिए दिक्रत यह है कि भारत ने भारी आयात शुल्क लगा रखा है। साथ ही अमरीका की जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के खतरे को देखते हुए इस पर पर भारत में पाबंदी है। अब ट्रंप की दादागिरी के सहारे अमरीकी कृषि उत्पाद अपना माल भारत पर थोपने की कोशिश में हैं। कोशिश यह है कि अमरीका से होने वाले द्विपक्षीय समझौते में कुछ फसलों को भी शामिल कर लिया जाए। हर कोई जानता है कि ये फसलें कौन सी होंगी। सोयाबीन और मक्का के अलावा अमरीका की मुख्य दिलचस्पी कपास में होगी। साथ ही 'वॉशिंगटन सेब', अमरीकी नाशपाती और कैलिफोर्निया के बादाम जैसे कुछ उत्पाद भी होंगे। फिलहाल अमरीका को गेहूं और दूध उत्पाद भारत में बेचने की कम गुंजाइश दिखती है लेकिन भविष्य में यह भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं। इस आयात को वकालत सिर्फ अमरीका ही नहीं, भारत की कुछ कंपनियां भी कर रही हैं। पोट्टी उद्योग, मांस निर्यातकों और कपड़ा मिलों के मालिक भी चाहते हैं कि उन्हें सस्ते दाम पर माल मिले और उनका मुनाफा बढ़े। अगर इसका किसी को नुकसान है तो भारत के किसान को। पहले ही किसान अपनी फसल के वाजिब दाम से वंचित रहता है। ऐसे में अगर अमरीका जैसे बड़े देश के साथ कृषि व्यापार खुल गया तो भारत का किसान दोहरी मार झेलेगा। पिछले कुछ साल में मक्का उत्पादन अपने परंपरागत क्षेत्रों के बढ़कर बिहार और बंगाल तक पहुंचा है।

वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी

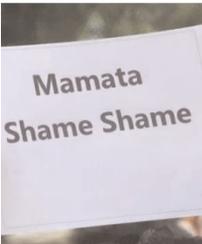
नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष के सभी लोगों ने बिल को स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब इसमें खामिया हैं। जिसको लाठी उसको भेंस ये हर वक्त ठीक नहीं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दो याचिका लगाई गई। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यह याचिका लगाई है। बिल पर 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा-राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। इसे अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद यह कानून बन जाएगा। राज्यसभा से गुरुवार को बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तमिलनाडु की डीएमके ने भी याचिका लगाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने को एक बड़ा सुधार बताया। उन्होंने शुरुवार सुबह एक पत्र लिखा कि यह कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और गरीब-पसमादा मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा- वक्फ संपत्तियों में सालों से गड़बड़ी हो रही थी, जिससे खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को नुकसान हुआ। यह नया कानून इस समस्या को दूर करेगा।

बंगाल सिलेंडर ब्लास्ट, पटाखा फैक्ट्री मालिक का भाई गिरफ्तार

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के पाथर प्रतिमा इलाके में 31 मार्च की देर रात सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। यह मुख्य आरोपी और पटाखा फैक्ट्री मालिक का भाई है। इससे पहले 2 अप्रैल को मुख्य आरोपी चंद्रकांत बानिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों भाई घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे। पुलिस अब दोनों भाइयों से मामले में पूछताछ कर रही है। इससे पहले 1 अप्रैल को पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए शुरुआती जांच में 2 गैस सिलेंडर में ब्लास्ट की जानकारी होने की बात कही थी। वहीं, भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि यहां करूड बम बनाने की अवैध फैक्ट्री चल रही थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन घटना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, एस्पपी कोटेडेश्वर राव ने कहा था कि घर में कोई अवैध पटाखा फैक्ट्री नहीं थी। टीएमसी विधायक समीर कुमार का घटना के बाद कहना था कि पीड़ित परिवार का घर से कुछ मीटर की दूरी पर लाइसेंस पटाखा फैक्ट्री थी। हो सकता है कि घर में पटाखों का कच्चा माल रखा गया हो, जिससे यह हादसा हुआ हो।

भाजपा बोली- ममता बनर्जी को जेल भेजेंगे

कोलकाता (एजेंसी)। भाजपा ने शुरुवार को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और उन्हें जेल भेजने की मांग की। भाजपा ने सिलीगुड़ी में विरोध रैली निकाली। इस दौरान विधायक शंकर घोष ने कहा, हम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हैं। पूरे मंत्रिमंडल पर दर्ज किया जाना चाहिए। अधिकतर मंत्रियों पर पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है। वे जेल जा रहे हैं, तो फिर ममता पर क्यों नहीं। वहीं, केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल



भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि ममता बनर्जी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में जेल जाने वाली दूसरी मुख्यमंत्री होंगी। हरियाणा के चार बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला ऐसे ही एक

मुख्यमंत्री का दतिया में शराबबंदी लागू करने पर हुआ भव्य नागरिक अभिनंदन

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम के विचार वाली भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व को परिवार मानती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस सिद्धांत पर चल रही राज्य सरकार सभी के हित और कल्याण के लिए समर्पित है। परिवारों का वातावरण खराब न हो, मेहनत से कमाए गए पैसे का उपयोग परिवार के हित में हो, यह सुनिश्चित करने के लिए ही शराबबंदी लागू की गई है। धार्मिक नगरों में पवित्र भाव को अनुभूति होती है, अतः प्रदेश में विद्यमान 19 देव-स्थानों की गरिमा को बनाए रखने के लिए ही इन स्थानों पर शराबबंदी लागू की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव माँ पीताम्बरा की नगरी दतिया में शराबबंदी लागू करने के लिए आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में जन-प्रतिनिधियों और नागरिकों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दतिया में शराबबंदी के लिये नागरिक अभिनंदन किया।



मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दतिया सहित प्रदेश में जहां-जहां देवी मां की कृपा है, वहां देवी लोक विकसित किए जाएंगे। चित्रकूट सहित भगवान श्रीराम से जुड़े प्रदेश के सभी स्थानों का श्रीराम वनपथ गमन मार्ग के अंतर्गत उन्नयन किया जा रहा है। इसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण की जहां-जहां भी लीलाएं हुईं, उन स्थानों को भी तीर्थ के रूप में विकसित करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सनातन संस्कृति के मूल भाव सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः के अनुरूप राज्य सरकार सबके कल्याण के लिए ही समर्पित भाव से काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। राज्य सरकार के लिए कृषकों का हित सर्वोपरि है, किसानों को उनकी मेहनत और उपज का सही दाम मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए ही 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीदा जा रहा है।

सोशल मीडिया पर बच्चों के बैन की याचिका खारिज

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुवार को 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस आंग्स्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा- यह नीतिगत मामला है। आप संसद से कानून बनाने के लिए कहें। यह हमारे दायरे से बाहर है। हालांकि कोर्ट ने अन्य अर्थारिटी के सामने अपील करने की छूट दी है। पीठ ने कहा कि आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार अपील की जा सकती है।

वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 8 राज्यों में प्रदर्शन

नई दिल्ली (एजेंसी)। वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास होने के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शुरुवार को जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम में मुस्लिमों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें महिला-बच्चे भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। फ्लैग मार्च जारी है। लखनऊ में दरगाहों और मस्जिदों की झुन से निगरानी की जा रही है। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी को वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकी मिली। उनके बहनोई को पीटा गया। गुजरात के अहमदाबाद में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर जुटे। उनके पोस्टर-बैनर पर वक्फ बिल



वापस लो, रिजेक्ट यूसीसी लिखा था। लोगों ने बांह पर काली पट्टे बांधी हुई थी। भीड़ ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पार्क सर्कस क्रासिंग में हजारों लोग सड़कों पर जमा हुए। यहां भी वक्फ बिल रिजेक्ट के बैनर-पोस्टर लिए लोग विरोध कर रहे हैं।

वक्फ बिल का विरोध, 7 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू छोड़ी

पटना (एजेंसी)। जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार का समर्थन किया है। इसके बाद से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है। बगवत शुरू हो गई है। एक के बाद मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा जारी है। अब तक बिल को समर्थन देने से नाराज 7 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें पूर्व प्रदेश सचिव एम. राजू नैयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, बेतिया जिला के उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव सिएन मो. तबरेज सिद्दीकी अली, भोजपुर से पार्टी

सदस्य मो. दिलशान राईन और खुद को मोतिहारी के ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी बताने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल हैं। नवादा जिले के जेडीयू जिला सचिव मोहम्मद फिरोज खान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फिरोज खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दोहरी नीति का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है। मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल के समर्थन पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। हालांकि, पार्टी ने दावों को खारिज किया है।

इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड (चुनावी बॉन्ड) से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। याचिका में कोर्ट से उसके पुराने फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। पुराने फैसले में कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिले 16,518 करोड़ रुपये जब्त करने की मांग खारिज की थी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 2 अप्रैल, 2024 के शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ खेम सिंह भाटी द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी, 2024 को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग के साथ फंडिंग में मिले रूपयों का डेटा साझा किया था। चुनाव आयोग ने 14 मार्च, 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया था।

17 राज्यों में आंधी, झारखंड में ओले गिरने का अलर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। मौसम विभाग ने शुरुवार के लिए बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 17 राज्यों में आंधी और तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है। झारखंड में ओले गिरने के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा देश के दक्षिणी राज्यों में तेज बारिश की आशंका है। गुजरात में हीट वेव और उमस बनी रह सकती है। बीते दिन कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना के अलग-अलग इलाकों में बारिश हुई।



बारिश के बाद कर्नाटक के अधिकतम तापमान में 7.5ए तक की गिरावट देखी गई। इधर, राजस्थान में आंधी-बारिश देखने को मिली। हालांकि, बाइपेर, जैसलमेर के इलाकों में गर्मी बढ़ने लगी है। तेलंगाना के यादाद्री-भुवनेश्वरी जिले में 97.8 एमएम बारिश हुई। वहीं, हैदराबाद में 91 एमएम हुई। इस वजह से चारमीनार के प्लास्टर का एक हिस्सा टूट गया।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी जुलूस की इजाजत दी

कोलकाता (एजेंसी)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को रामनवमी पर 6 अप्रैल को हावड़ा में तय रूट पर जुलूस निकालने की सशर्त इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जुलूस में हथियार लेकर नहीं आएगा। पुलिस जुलूस की निगरानी करेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने फौरन आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया कि रामनवमी के जुलूस में कोई भी हथियार लेकर नहीं निकलेगा। भाजपा के सियासी रूप से मजबूत गढ़ उत्तर बंगाल के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहाड़ी जिलों में ज्यादा फोर्स लगाई गई है। रामनवमी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने भी 9 अप्रैल तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। छरूममता बनर्जी ने सभी समुदाय के लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। दक्षिण बंगाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुप्रतिम सरकार ने बताया कि हमें रामनवमी की आड़ में अशांति फैलाने की साजिश का खुफिया इनपुट मिला है।

केंद्र ने तमिलनाडु के नीट से छूट संबंधी विधेयक को नामंजूर किया-मुख्यमंत्री स्टालिन

नई दिल्ली (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुरुवार को कहा कि राज्य को नीट से छूट संबंधी विधानसभा से पारित किये गये प्रस्ताव को केंद्र ने नामंजूर कर दिया है। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने विधानसभा से पारित कराने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा था। स्टालिन ने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को समाप्त कराने को लेकर तमिलनाडु अपना संघर्ष जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में नौ अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा को



नवीनतम घटनाक्रम से अवगत कराते हुए प्रस्ताव को नामंजूर किये जाने को काला अध्याय करार दिया। उन्होंने केंद्र पर तमिलनाडु की जनता की इच्छा तथा विधानसभा के विधेयक की अवहेलना करने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से सभी आवश्यक स्पष्टीकरण दिए थे, फिर भी केंद्र सरकार ने नीट से छूट के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया।

जयपुर सीरियल ब्लास्ट में जिंदा बम मामले में 4-आतंकी दोषी

जयपुर (एजेंसी)। जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में अदालत ने चार आतंकीयों को दोषी ठहराया है। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत में जज रमेश कुमार जोशी जिंदा बम प्लांट करने के मामले में चारों आतंकीयों को लेकर फैसला मंगलवार, 8 अप्रैल को सुनाएंगे। अदालत ने जिंदा बम केस में सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी ठहराया है। इनमें शाहबाज को छोड़कर अन्य को सीरियल ब्लास्ट के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। फांसी की सजा के मामले में राज्य सरकार की अपील सुप्रीम



कोर्ट में पेंडिंग है। 13 मई को 2008 को जयपुर में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, नौवा बम चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था। बम फटने

के 15 मिनट पहले इसे डिफ्यूज कर दिया गया था। चारों आतंकीयों को 4 धाराओं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट

(यूपीए) की दो, विस्फोटक पदार्थ कानून की 3 धाराओं में दोषी ठहराया गया है। इन धाराओं में अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है।

क्या शिखर धवन को मिल गया दूसरा प्यार?

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं और एक बार फिर उन्हें प्यार हो गया है। धवन की लव अफेयर के चर्चा काफी समय से चल रहे हैं। उन्हें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एक मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट किया गया था उस दौरान से ही उनके अफेयर के चर्चे चल रहे हैं। वहीं इन दोनों को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रूफ मैच में भारत के बांग्लादेश के खिलाफ मैच के साथ देखा गया था। इन दोनों की एक-साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसमें महिला को जब करबी से जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये सोफी शाइन है

कगिसो रबाडा आईपीएल छोड़ साउथ अफ्रीका लौटे

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल 2025 में आरसीबी को हराकर अपनी दूसरी जीत का स्वाद चखने वाली गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा महज 2 मैच खेलकर निजी कारणों से आईपीएल छोड़ स्वेडिश लौट गए हैं। उनकी टीम गुजरात टाइटंस ने गुरुवार को ये जानकारी दी। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली जोटी ने नहीं बताया है कि रबाडा कब तक लौटेंगे? गुजरात टीम ने एक बयान में कहा कि, कगिसो रबाडा कुछ अहम निजी मसले से निपटने के लिए साउथ अफ्रीका लौट गए हैं। रबाडा ने पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक एक विकेट लिया था। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के खिलाफ

जो कि आयरलैंड की हैं। अब धवन ने अपने रिलेशन पर खुलकर बात कही है। दरअसल, धवन ने एक शो में कहा कि हां मैं लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं प्यार के मामले में बदकिस्मत था। बल्कि, मेरी पसंद कम अनुभव से आई थी। लेकिन अब मेरे पास अनुभव है और वह काम आया। ये मेरे लिए सीखने का एक मौका था। मैं हमेशा प्यार में रहता हूँ। वहीं जब धवन से पूछा गया कि क्या वह फिर से प्यार करने के लिए तैयार हैं तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि, मैं जानता हूँ कि क्रिकेट में बाउंसर से कैसे बचना है और मैं जानता हूँ कि अब आप मुझ पर बाउंसर फेंक रहे हैं।

बुधवार को बंगलुरु में खेले गए मैच में टीम में जगह नहीं दी गई। रबाडा की जगह अरशद खान को उतारा गया जिन्होंने विराट कोहली का कीमती विकेट झटका। अभी तक रबाडा ने दो ही मैच खेले हैं। उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में 4 ओवर में 41 रन देकर एक विकेट झटका। जबकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 42 रन देकर एक विकेट लिया। इस मैच में रबाडा ने 5 गेंदों में सात रन बनाए। फिलहाल, गुजरात टाइटंस की आईपीएल के 18वें सीजन में शुरुआत अच्छी नहीं हुई। टीम को पहले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ 11 रनों से हार झेलनी पड़ी। इसके अगले मैच में शुभमन गिल की टीम ने पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को माद दी।

सारा तेंदुलकर ने ग्लोबल ई-क्रिकेट प्रीमियर लीग में खरीदी मुंबई की टीम

नई दिल्ली (एजेंसी)। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर भी अब क्रिकेट में कूद गई हैं। दरअसल, सारा ने ग्लोबल ई-क्रिकेट प्रीमियर लीग में मुंबई फेंचाइजी खरीदी है। जोईपीएल ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फैंस को इसके बारे में बताया। ई-क्रिकेट लीग की दुनिया में ग्लोबल ई-क्रिकेट प्रीमियर लीग सबसे बड़ी लीग में से एक है। पहले ही सीजन में ग्लोबल ई-क्रिकेट प्रीमियर लीग ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। ग्लोबल ई-क्रिकेट प्रीमियर लीग के पहले सीजन

में 2 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था लेकिन 2025 में कुल 910000 खिलाड़ियों के अपना नाम दर्ज करवाया है। जोईपीएल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि सारा तेंदुलकर ने ग्लोबल ई-क्रिकेट प्रीमियर लीग में मुंबई फेंचाइजी को खरीदा है। मुंबई की मालकिन बनने के बाद सारा तेंदुलकर ने कहा कि, क्रिकेट हमारे परिवार का अभिन्न अंग रहा है। ई-स्पोर्ट्स में इसकी संभावनाओं को तलाशना रोमांचकारी है। जोईपीएल ने मुंबई फेंचाइजी की मालकिन होना एक सपना सच होने जैसा है।

ये 3 खिलाड़ी हासिल कर सकते हैं पीकेएल में 1500 रेड पॉइंट्स

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रो कबड्डी लीग में अभी तक मात्र दो ही रेडर ऐसे हुए हैं जिन्होंने 1500 रेड पॉइंट्स हासिल करने का कारनामा किया हुआ है। सबसे पहले परदीप नरवाल ने ये कारनामा किया था। परदीप नरवाल पीकेएल में 1800 से भी ज्यादा पॉइंट्स ले चुके हैं। उनके नाम प्रो कबड्डी लीग इतिहास में सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स लेने का रिकॉर्ड है। इसके बाद मनिंदर सिंह का नंबर आता है। उन्होंने 1528 रेड पॉइंट्स अभी तक हासिल किए हैं। अब फैंस के मन में सवाल ये है कि इन दोनों के अलावा और कौन-कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस आंकड़े को हासिल कर सकते हैं। प्रो कबड्डी लीग में युवा रेडर नवीन कुमार बहुत जल्द ही 1500 के आंकड़े को क्रॉस कर सकते हैं। नवीन कुमार ने अभी तक काफी जबरदस्त खेल दिखाया है। उन्होंने 107 मुकाबले अपने पीकेएल करियर में खेले हैं और इस दौरान 1102 रेड पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं। इससे पता चलता है कि उनका

प्रदर्शन कितना बढ़िया रहा है। नवीन कुमार भी बहुत जल्द 1500 के आंकड़े को हासिल कर सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अर्जुन देशवाल हैं जो अपने करियर में अभी तक 1174 रेड पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं। अर्जुन देशवाल ने जयपुर पिक पैथर्स को पीकेएल का टाइटल जिताने में अहम योगदान दिया था। उनका प्रदर्शन पीकेएल में लगातार अच्छा रहा है। अर्जुन देशवाल जिस हिसाब से खेल रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वो पीकेएल में जल्द ही 1500 का आंकड़ा हासिल करलेंगे। पवन सेहरावत प्रो कबड्डी लीग के जबरदस्त रेडर्स में से एक हैं। वो अभी तक 1318 रेड पॉइंट्स अपने करियर में हासिल कर चुके हैं। वो ओवरऑल तीसरे सबसे ज्यादा रेड पॉइंट हासिल करने वाले खिलाड़ी हैं। परदीप नरवाल और मनिंदर सिंह के बाद 1500 रेड पॉइंट्स तक पहुंचने वाले वो तीसरे प्लेयर बन सकते हैं। अगले ही सीजन में वो ये कीर्तिमान हासिल कर सकते हैं।



दोनों हाथ से गेंदबाजी करने वाले अनोखे गेंदबाज का आईपीएल डेब्यू



नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल इतिहास में अजब गजब टैलेंट आता रहा है। अब आईपीएल के 18वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद को एक अनोखा प्लेयर मिला है जो

दोनों हाथों से गेंदबाजी कर लेता है। अपनी इसी खूबी के कारण वह चर्चा में है। गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। जिसमें

कामिंदु मेंडिस ने अपना आईपीएल डेब्यू किया। दरअसल, वो पहले भी दोनों हाथों से बॉलिंग करने के कारण सुर्खियों में बने रहे हैं। अब आईपीएल यूनिवर्स को भी उन्होंने अपना टैलेंट दिखा दिया है। गजब की बात ये है कि उन्होंने एक ही मैच के एक ही ओवर में 2 अलग-अलग तरह से गेंदबाजी की है। श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस ने कोलकाता के खिलाफ मैच में दाएं और बाएं हाथ से भी गेंदबाजी की। ये बात है कि कोलकाता की पारी के 12वें ओवर की, जिसमें कामिंदु गेंदबाजी करने आए। कोलकाता के लिए क्रीज पर अंगकृष रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर मौजूद

थे। जब रघुवंशी खेल रहे थे तब मेंडिस ने बाएं हाथ से गेंदबाजी की वहीं जब अगली ही गेंद पर वेंकटेश अय्यर स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे तो मेंडिस ने ना केवल एंगल बदला बल्कि दाएं हाथ से गेंदबाजी कर सबको चौंका दिया था। बता दें कि, पिछले साल जुलाई में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गई टी20 सीरीज में कामिंदु मेंडिस ने गेंदबाजी की थी। उस समय टीम इंडिया के खिलाफ मैच में मेंडिस ने सूर्यकुमार यादव को बाएं हाथ से गेंदबाजी की थी वहीं जब रिकू सिंह खेल रहे थे तब मेंडिस ने दाएं हाथ से गेंदबाजी करनी शुरू कर दी थी।

जुलाई में इटली में खेले जाएगी होपमैन कप मिश्रित टीम टेनिस प्रतियोगिता



नई दिल्ली (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने घोषणा की है कि इस साल का होपमैन कप इटली के दक्षिणी शहर बारी में खेला जाएगा। इस मिश्रित टीम टूर्नामेंट में इटली, फ्रांस, स्पेन, यूनान, कनाडा और मौजूदा चैंपियन क्रोएशिया की टीमों हिस्सा लेंगी। इसका आयोजन विंबलडन के एक सप्ताह बाद 16 से 20 जुलाई तक किया जाएगा। होपमैन कप के लिए टीमों में एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी शामिल होते हैं। इसके एक मुकाबले में एक पुरुष एकल मैच, एक महिला एकल मैच और एक मिश्रित युगल मैच शामिल होता है। इस टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को रैंकिंग अंक नहीं मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी हैरी होपमैन के नाम पर, होपमैन कप 1989 में शुरू हुआ और 2020 तक हर साल खेला जाता था। पहले 30 वर्ष तक इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में टेनिस सत्र के पहले सप्ताह में किया जाता था। आखिरी बार इसका आयोजन 2023 में फ्रांस में हुआ था जिसमें क्रोएशिया के डोना वेकिच और बोर्ना कोरिच चैंपियन बने थे।

विराट कोहली की चोट को लेकर आरसीबी हेड कोच एंडी फ्लावर ने दिया बड़ा अपडेट,



नई दिल्ली (एजेंसी)। गुजरात टाइटंस ने बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। रजत पाटीदार के नेतृत्व वाली आरसीबी की टीम की ये आईपीएल 2025 में पहली हार है। टीम ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं। बंगलुरु में खेले गए पहले

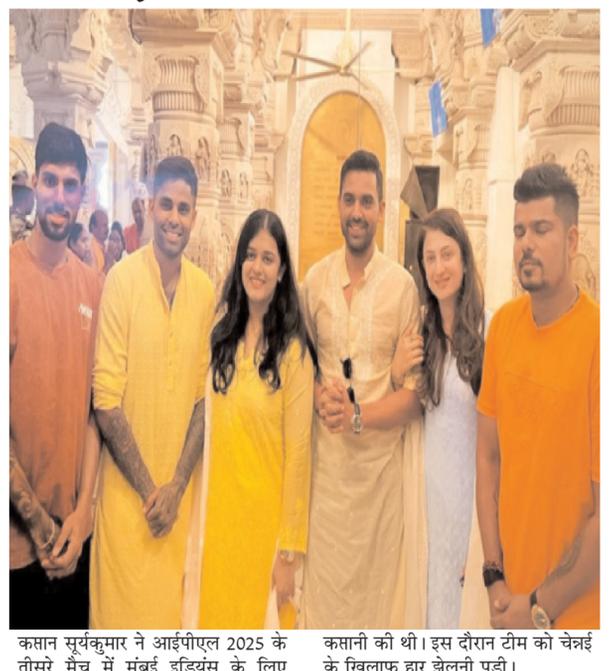
मुकाबले के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली को अंगुली में चोट लगी, जिसे देकर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद फैंस टेंशन में आ गए। हालांकि, टीम के हेड कोच एंडी फ्लावर ने कहा है कि चिन्ता की बात नहीं है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ

मुकाबले में फील्डिंग करते समय विराट कोहली को अंगुली में चोट लगी। लेकिन फ्लॉवर ने कहा कि स्टाफ बल्लेबाज की हालत को लेकर कोई गंभीर चिन्ता की बात नहीं है। फ्लॉवर ने मैच के बाद कहा कि, विराट कोहली ठीक लग रहे हैं, वह ठीक हैं, कोई चिन्ता की बात नहीं है। मैच

के बाद फ्लॉवर ने कहा कि, विराट ठीक लग रहे हैं, वह ठीक हैं, चिन्ता की कोई बात नहीं है। आरसीबी को ये मैच आठ विकेट से गंवाना पड़ा जो तीन मैचों में सत्र की उनकी पहली हार थी। गुजरात की पारी के दौरान विराट कोहली ने डीप में बाउंड्री बचाने की कोशिश की लेकिन इस दौरान उनकी अंगुली में चोट लगी। फीजियो ने उनका ट्रीटमेंट किया, इस दौरान वह दर्द में दिखे। आरसीबी के मुख्य कोच एंडी फ्लावर ने कहा कि पहले सात ओवरों में चार विकेट खोने से उनकी टीम के लिए परिस्थितियों मुश्किल हो गई थी। फ्लॉवर ने संवाददाताओं से कहा कि, हमने पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी की लेकिन इस बीच हमने कुछ अहम विकेट गंवाए। इससे मैच का पासा पलट गया। अगर आप पावर प्ले में अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो इससे आपके लिए परिस्थितियों मुश्किल हो जाती हैं।

अयोध्या पहुंचकर मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने किए रामलला के दर्शन

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल की पांच बार की विजेता टीम मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। जिसके लिए टीम लखनऊ पहुंच चुकी है। इसी दौरान टीम के कुछ खिलाड़ी गुरुवार को अयोध्या पहुंचे जहां उन्होंने राम लला के दर्शन किए। खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर मंदिर के दर्शन करने के बाद की तस्वीरें शेयर की हैं। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल में ये चौथा मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए टीम बुधवार को लखनऊ पहुंच गई थी। तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, दीपक चाहर और कर्ण शर्मा जैसे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल 2025 के मुकाबले से पहले अयोध्या राम मंदिर का दौरा किया। उनके साथ सूर्यकुमार की पत्नी देविश शेट्टी और चाहर की पत्नी जया भी थीं। मुंबई इंडियंस फेंचाइजी ने एक्स पर खिलाड़ियों और उनके परिवार की तस्वीरें शेयर की हैं। सूर्यकुमार यादव ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी के साथ की तस्वीर शेयर की। इस दौरान उन्होंने कैप्शन में लिखा कि, जय भगवान राम। भारतीय टी20 टीम के



कसान सूर्यकुमार ने आईपीएल 2025 के तीसरे मैच में मुंबई इंडियंस के लिए

कसान की थी। इस दौरान टीम को चेन्नई के खिलाफ हार झेलनी पड़ी।

परिजन का आरोप पुलिस की पिटाई के बाद बाहर नहीं निकले

मऊगंज में घर के अंदर फांसी पर लटके मिले पिता सहित दो बच्चों के शव, पुलिस पर शक

मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)। मऊगंज जिले के गडरा गांव के एक घर में तीन शव मिले हैं। बदन पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस गेट खोलकर अंदर गई तो तीन शव फंदे से झूल रहे थे। उनकी पहचान ओसेरी साकेत, उसकी बेटी मीनाक्षी (11) और बेटे अमन (8) के रूप में हुई है। ओसेरी के भाई की पत्नी का कहना है कि पिछले दिनों हिंसा के बाद गांव में सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस ने जेट से मारपीट की थी। उसी दिन से उन्होंने घर का गेट नहीं खोला। वो अपने से फांसी नहीं लगाए हैं। इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। बता दें, ये वही गडरा गांव है, जहां 15 मार्च को पीट-पीटकर एक युवक की हत्या के बाद हिंसा में एएसआई की मौत हो गई थी।

रीवा आईजी गौरव राजपूत ने बताया, ओसेरी साकेत के घर से बदन आ रही थी। घर के अंदर ओसेरी, बेटी मीनाक्षी (11) और बेटे अमन (8) के शव मिले हैं। पारिवारिक कारणों के चलते सामूहिक सुसाइड का मामला लग रहा है। 15 मार्च को हुई हिंसा से यह मामला पूरी तरह से अलग है।

वहीं पड़ोसियों ने बताया, आज सुबह से घर से बदन आ रही थी। खिड़की से झांकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रीवा से फॉरेंसिक टीम और अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया है।

पहली पत्नी की मौत, दूसरी छोड़कर गई: जानकारी के अनुसार, ओसेरी की पहली पत्नी की मौत हो



परिजन बोले- घर में घुसकर मारती थी पुलिस

कुसुमकली ने बताया, जेट और उनके बच्चों के शव मिले हैं। हम दो किलोमीटर दूर रहते हैं। यहां गांव में 15 मार्च को विवाद हुआ था, इसके बाद से कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। गांव में जो पुलिस तैनात थी वो लोगों को घर में घुसकर मारती थी। महिलाओं को भी पीटा जाता था। पुलिस ने जेट से भी मारपीट की थी।

चुकी है। उसके चार बच्चे बाहर रहते हैं। दूसरी पत्नी से दो बच्चे थे।

एसपी दिलीप सोनी बोले- पुलिस का कोई लेना-देना नहीं है

एसपी दिलीप सोनी ने बताया, गडरा में साकेत समाज की बस्ती से घर से बदन आने की सूचना मिली थी। पुलिस पहुंची तो घर अंदर से बंद था। आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने दरवाजा खोला। अंदर तीन डेडबॉडी थीं। शवों का आइडेंटिफिकेशन करा रहे हैं। पोस्टमॉर्टम के लिए बॉडी भेजी है। फॉरेंसिक टीम से जांच कराई गई है। घटना का कारण पता कर रहे हैं। पुलिस का इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है।

वह भी छोड़कर चली गई। ओसेरी दो बच्चों के साथ रह रहा था। सिलाई का काम करके वह परिवार का भरण पोषण करता था।



'सुरक्षा करने वाली पुलिस ने फांसी पर लटका दिया'

मृतक ओसेरी के परिजन रामकली साकेत ने कहा, पुलिस कहती थी कि किसी के घर मत जाना। किसी को अपने पास मत बैठाना, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। हिंसा के बाद पुलिस ने घर में घुसकर लोगों को पीटा है। छोटे-छोटे बच्चों को उठाकर खेत में फेंक दे रहे थे। रात में पुलिसवाले घर में घुसकर महिलाओं को मार रहे थे। कुड़ी लगाकर पीटा है।

समय पर फायर ब्रिगेड पहुंच जाती, तो जलने से बच जाती गृहस्थी



मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)। जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सगरा में शुक्रवार दोपहर एक घर में भीषण आग लग गई। इस घटना में लगभग 10 लाख रूप से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लवकुश मिश्रा के घर में लगी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोगों को आग की जानकारी उस समय हुई जब मकान से घना धुआं निकलने लगा। थोड़ी ही देर में मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने अपने-अपने घरों से बाल्टियां लाकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा घर जलकर राख हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही सगरा थाना प्रभारी अकिता मिश्रा

पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंची, तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था।

पॉइंट लवकुश मिश्रा ने प्रशासन पर देर से प्रतिक्रिया देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय पर फायर ब्रिगेड पहुंच जाती, तो आग पर काबू पाया जा सकता था और नुकसान को टाला जा सकता था।

थाना प्रभारी अकिता मिश्रा ने बताया कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

पुराने बस स्टैंड-ढेकहा तिराहे तक फ्लाई ओवर का मुद्दा लोकसभा में उठाया

मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)। सांसद जनार्दन मिश्रा ने लोकसभा के शून्य काल में पुराने बस स्टैंड से ढेकहा तिराहे तक फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण का मुद्दा उठाया। इस प्रस्तावित फ्लाईओवर की घोषणा पहले ही डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल बोदाबाग ओवरब्रिज के लोकार्पण के दौरान कर चुके हैं। सदन में मिश्रा ने कहा- प्रस्तावित मार्ग पर हजारों वाहनों की दैनिक आवाजाही से, विशेषकर सुबह-शाम गंभीर जाम की स्थिति बनती है। यह क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन जाम की समस्या से लोगों का समय और ईंधन दोनों बर्बाद होते हैं।



बता दें कि, स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को लेकर सांसद ने केंद्र सरकार से परियोजना की शीघ्र स्वीकृति और बजट आवंटन का आग्रह किया। उनका कहना है कि यह फ्लाईओवर न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि आसपास के जिलों से आने वाले यात्रियों के लिए भी राहतकारी साबित होगा।

मऊगंज मनरेगा प्रभारी एपीओ को कलेक्टर ने हटाया

नईगढ़ी जनपद में किया अटैच, वीडियो में रिश्तत लेते दिखी थी नीतू सिंह

मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)। मऊगंज जनपद पंचायत में मनरेगा प्रभारी एपीओ नीतू सिंह का पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कलेक्टर संजय जैन ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से नीतू सिंह को मऊगंज से हटाकर नईगढ़ी जनपद पंचायत में अटैच कर दिया है। मामला 2 अप्रैल का है, जब नीतू सिंह का पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस मामले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 24 घंटे के भीतर जांच समिति गठित कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे। रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है।

अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने व्यक्त किया शोक

मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)। भारत के सिनेमा जगत को राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करने वाले महान अभिनेता, निर्माता-निर्देशक मनोज कुमार के निधन पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने गहन शोक व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि भारत की बात सुनाने वाली आवाज आज खामोश हो गई। उन्होंने कहा कि मनोज



नीतू सिंह, एपीओ

ग्राम देवरी के लाभार्थी मंगल सिंह और त्रिगुणानारायण मिश्रा ने शिकायत की है कि नंदन फल योजना के तहत पौधा रोपण में लाभ दिलाने के लिए नीतू सिंह ने उनसे 4,000 रुपए की रिश्तत मांगी थी। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, जांच रिपोर्ट आने तक नीतू सिंह को नईगढ़ी जनपद पंचायत में किसी भी शाखा का दायित्व नहीं दिया जाएगा। नवनि्युक्त कलेक्टर संजय जैन की इस कार्रवाई से जनता में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीदें जगी हैं।

मानसभवन में जिला प्रशासन की तरफ से पुस्तक मेले का आयोजन

पुस्तक मेले में असंतुष्ट दिखे अभिभावक

एक ही स्थान में सभी विद्यालयों की पुस्तकें एवं गणवेश रिाययती दर पर उपलब्ध कराने का खोखला दावा

पुस्तक एवं गणवेश मेला का कलेक्टर ने किया शुभारंभ

मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)। शहर के मानसभवन में जिला प्रशासन की तरफ से पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। जिसमें शहर में निजी संचालित स्कूलों की किताबों को डिस्काउंट में देने का दावा किया गया। इस पुस्तक मेले में कई किताब-कापी बेचने वाली दुकानों के स्टाल लगे, काफी संख्या में लोग किताब-कापियां लेने के लिए पहुंचे लेकिन ज्यादातर अभिभावक इस आयोजन से संतुष्ट नहीं रहे, क्योंकि उन्हें जिन स्कूलों की किताबें चाहिए थी वो मिल ही नहीं पाई। इसके लिए उन्हें दुकान जाने के लिए ही कहा गया। पुस्तक मेले में लोगों ने सिर्फ 10 फीसदी डिस्काउंट के साथ कापियां ही खरीदीं। हालांकि कुछ ही स्टाल में अभिभावकों को उनके बच्चों के स्कूल के सिलेबस के अनुसार



किताबें मिलीं। दावा यह किया गया था कि हर स्टाल में हर स्कूल की किताब मिलेगी लेकिन आलम यही रहा कि जिनसे स्कूलों की साठ-गांठ है उनकी ही स्टॉल में उन स्कूलों की किताबें मिल रही थीं वो भी पूरी नहीं (लोगों ने कहा इससे अच्छा तो दुकान से जाकर ही किताबें ले लेते हैं)।

पुस्तक मेले के शुभारंभ के उपरांत कलेक्टर ने पुस्तक व ड्रेस विक्रेताओं से चर्चा की तथा निर्देश दिये कि निर्देशानुसार विद्यालयों की सभी पुस्तकें उपलब्ध करावें जिससे अभिभावक को पुनः किताब खरीदने न आना पड़े। इस दौरान उन्होंने अभिभावकों व विद्यार्थियों से भी संवाद किया। विद्यार्थियों एवं उनके परिजनों ने कलेक्टर को इस पहल के लिये धन्यवाद दिया, लेकिन जब वह पुस्तक मेले में किताबें सहित अन्य सामग्री लेने पहुंचे तो उन्हें मायूसी हाथ लगी। हालांकि पुस्तक मेला के भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने विक्रेताओं के स्टाल का निरीक्षण

भटकते रहे अभिभावक

प्रशासन ने भले ही पुस्तक मेला लगाकर अभिभावकों को सुविधा देने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत है कि अभिभावक दिनभर परेशान नजर आये। वो पुस्तक मेला और संबन्धित दुकानों के चक्कर लगाते हुये नजर आये। क्यों कि कीमतों में रियायत की बात तो दूर उन्हें किताबें ही नहीं उपलब्ध हो पा रही थीं। पुस्तक मेले में स्टॉक खत्म होने की बात ही जा रही थी और दुकानों में भेजा जाता था। और दुकानों में पहुंचने पर बोला जा रहा था कि स्टॉक समाप्त हो गया, दो-तीन दिन बात उपलब्ध हो पायेगी। इस तरह अभिभावक दिनभर बच्चों के साथ भटकते रहे। संबन्धित पुस्तकों की दुकानों पर देर शाम तक अभिभावकों की भीड़ जामा रही।

किया तथा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पुस्तक व ड्रेस विक्रय किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रत्येक स्टाल में विभागीय एक व्यक्ति की परिचय पत्र के साथ डीन मेडिकल कालेज डॉ. सुनील अग्रवाल एवं अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा आरपी सिंह तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने जिले में 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा की

गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के दिये निर्देश

मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले में 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्यों को पूर्ण करावें।

कलेक्टर के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने सिंचाई विभाग की नहरों के कार्य प्राथमिकता से पूर्ण कराने तथा भवन निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि टीआरएस कालेज में निर्माणाधीन भवनों की प्रगति धीमी है शीघ्रता से कार्य हो तथा स्वास्थ्य विभाग के केन्द्रों एवं छात्रावास भवनों के निर्माण कार्यों को संबंधित विभाग गति दें।



जिले में 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न विभागों के 57 कार्य स्वीकृत है।

कलेक्टर ने विभागवार एवं कार्यवार समीक्षा करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत मेडिकल कैम्पस में

निर्माणाधीन डॉक्टर्स क्वार्टर्स के कार्य में धीमी प्रगति पर निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के

निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने गुड औद्योगिक क्षेत्र में जून से पूर्व पाइप लाइन द्वारा जल की

उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया। विद्युत मंडल के आरडीएस योजना के तहत कार्यों तथा हाउसिंग बोर्ड द्वारा पुनर्व्यवस्थापन योजना से कराये जा रहे कार्यों की कलेक्टर ने बैठक में समीक्षा की। उन्होंने मेडिकल कालेज में निर्माणाधीन अकादमिक भवन को मेडिकल कालेज को शीघ्र हस्तांतरित करने के निर्देश पीआईयू को दिये। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर, डीन मेडिकल कालेज डॉ. सुनील अग्रवाल एवं अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा आरपी सिंह तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

अभियान में मनरेगा से जल संरक्षण के 1378 कार्य होंगे पूर्ण

मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)। जिले भर में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मनरेगा योजना से जल संरक्षण और संवर्धन के लिए पूर्व से स्वीकृत अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराया जाएगा। इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने बताया कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक विकासखण्ड में अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराने की कार्ययोजना बना ली गई है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मनरेगा से स्वीकृत 1378 जल संरक्षण के कार्यों को पूरा कराया

जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि मनरेगा से कराए जा रहे जल संरक्षण के कार्य जल गंगा संवर्धन अभियान की अवधि में अनिवार्य रूप से पूरे कराकर फोटोग्राफ सहित आवेदन प्रस्तुत करें। इसका विवरण नरगा पोर्टल तथा जल गंगा संवर्धन अभियान के पोर्टल पर भी अनिवार्य रूप से दर्ज करें। निर्माण कार्यों की प्रगति की हर सप्ताह रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा सभी सहायक यंत्री निर्माण कार्यों की सतत निगरानी करें।